राजीव रंजन और अन्य

बनाम

आर. विजयकुमार

(आपराधिक अपील संख्या 729-732/2010)

14 अक्टूबर, 2014

[जे. चेलमेश्वर और ए.के. सिकरी, जेजे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धाराएँ 197, 482 - कार्यवाही रद्द करना - बिजली बोर्ड द्वारा निविदा आमंत्रित की गई – अपीलार्थी संख्या 2, मुख्य अभियंता द्वारा जारी कार्य रिपोर्ट/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रत्यर्थी का निविदा आवेदन खारिज कर दिया गया - उनके आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए बिजली बोर्ड के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया - मुकदमा वापस ले लिया गया - प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया और उसके खिलाफ एसएलपी भी खारिज कर दी गई प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीओं के खिलाफ धारा 120 बी, 468, 420 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की कि प्रमाणपत्र झूठा और जाली था - सम्मन जारी करना - हालांकि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही अपास्त करने से इनकार कर दिया अपीलार्थी लोक सेवक हैं, उनके द्वारा किए गए कथित अपराध उनके सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं थे और इसलिए धारा 197 लागू नहीं हुई – अभिनिर्धारित: निविदा की अस्वीकृति अपीलार्थी द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को आगे बढ़ाने और उसके निर्वहन में थी - आपराधिक शिकायत दर्ज करने में प्रत्यर्थी की कार्रवाई प्रामाणिक नहीं थी और यह दुरूपयोग कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन थी - एक सिविल मामले को आपराधिकता का रंग देने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप शरारतपूर्ण ढंग से

लगाए गए थे – उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को अपास्त कर देना चाहिए था।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. धारा 197 दं.प्र.सं. में कहा गया है कि यदि कोई अपराध किसी लोक सेवक द्वारा किया गया है, जिसे सरकार की मंजूरी के बिना या उसके कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता है, न्यायालय को इस प्रावधान में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अलावा ऐसे अपराध का संज्ञान लेने से रोका जाता है। यदि लोक सेवक के खिलाफ कथित अपराध "अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का इरादा रखते हुए" किया जाता है, तो मंजूरी आवश्यक है। मौजूदा मामले में, निविदा समिति ने इस आधार पर निविदा खारिज कर दी थी कि प्रत्यर्थी पूर्व-योग्यता शर्तों को पूरा नहीं करता था। ऐसा करने से पहले, प्रत्यर्थी को बार-बार कार्य रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन वह अनुपालन करने में विफल रहा, जबकि उसने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। फिर भी, प्रत्यर्थी के दावे को सत्यापित करने और योग्यता के आधार पर उसकी बोली पर विचार करने के लिए, हालांकि इसकी सख्त आवश्यकता नहीं थी, अपीलकर्ता को जेएसईबी से वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने जेएसईबी के अधिकारियों से मुलाकात की और इस आशय की अपनी रिपोर्ट सौंपी कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कार्य संतोषजनक नहीं थे। यहां तक कि, उक्त पावर स्टेशन के महाप्रबंधक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आपूर्ति की गई स्कैनिंग प्रणाली में दोषों के कारण, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उक्त विद्युत बोर्ड प्रत्यर्थी द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों से संतुष्ट नहीं हैं। यहां तक कि तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी प्रत्यर्थी के खिलाफ गई क्योंकि उसकी राय थी कि प्रत्यर्थी तकनीकी जांच और तुलनात्मक डेटा पर तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं था। उसके आधार पर, प्रत्यर्थी के निविदा दस्तावेज को

खोलकर वापस नहीं किया गया और उसे तदनुसार सूचित किया गया। यह सब स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों को आगे बढ़ाने और उनके निर्वहन में हुआ। [पैरा 10,11,15] [993-जी-एच; 994-ए; 996-एफ एच; 997-ए-ई]

2. प्रत्यर्थी ने एक सिविल वाद दायर किया। हालांकि, वाद प्रत्याहरित कर लिया। एक बार जब वाद प्रत्याहरित किया जाता है, तो यह आदेश XXIII नियम 1 सीपीसी के प्रावधान के संबंध में रचनात्मक पूर्व-न्याय के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, जब आदेश IX नियम 8 सीपीसी के तहत वाद खारिज कर दिया जाता है, तो आदेश IX नियम 9 के तहत नया वाद वर्जित है। यहां तक कि जब प्रत्यर्थी ने स्वयं सिविल वाद में बर्खास्तगी का आदेश आमंत्रित किया, तब भी उसने दायर किया गैर-अभियोजन के लिए उनके मुकदमे को खारिज करने के सिविल न्यायालय में पारित आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका, लेकिन इसे उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। प्रत्यर्थी द्वारा की गई एसएलपी को भी खारिज कर दिया गया। जब वह उक्त प्रयास में सफल नहीं हुआ, तो वह जालसाजी के आरोपों के साथ सामने आया। इस प्रकार, आपराधिक शिकायत दर्ज करने में प्रत्यर्थी की कार्रवाई प्रामाणिक नहीं थी और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और उल्लंघन थी। प्रत्यर्थी द्वारा सिविल प्रकृति के एक मामले को आपराधिक अभियोजन में बदलने का प्रयास किया गया था। उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द न करके गलती की। [पैराज 16,18,19] [997-एच; 998-ए-एफ; 1000-सी-डी]

शंभू नाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1997) 5 एससीसी 326: 1997(2) एससीआर 1139; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 पूरक (1) एससीसी 335: 1991(1) पूरक एससीआर 387; भारतीय ऑयल कार्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (2006) 6 एससीसी 736: 2006(3) पूरक एससीआर 704; इंदर मोहन

गोस्वामी और एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य (2007) 12 एससीसी 1: 2007 (10) एससीआर 847-निर्भरता।

नरेश कुमार मदन बनाम एम.पी. राज्य (2007) 4 एससीसी 766 : 2007 (4) एससीआर 1040; महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. बुधिकोटा सुब्बाराव (1993) 2 एससीसी 567: 1993 (2) एससीआर 329- संदर्भित।

<u>मामला कानून संदर्भः</u>

2007 (4) एससीआर 1040	संदर्भित किया	पैरा 4
1993 (2) एससीआर 329	संदर्भित किया	पैरा 5
1997 (2) एससीआर 1139	भरोसा किया गया	पैरा 13
1991 (1) पूरक एससीआर 387	भरोसा किया गया	पैरा 17
2006 (3) पूरक एससीआर 704	भरोसा किया गया	पैरा 18
2007 (10) एससीआर 847	भरोसा किया गया	पैरा 19

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 729-732/2010

मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै द्वारा आपराधिक मूल याचिका (एमडी) संख्या 9890, 10017, 10027 और 10028 ऑफ़ 2008 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.06.2009 से उत्पन्न।

राहुल श्रीवास्तव, राम स्वरूप शर्मा, अपीलार्थियों की ओर से।

आर. विजयकुमार (प्रत्यर्थी-व्यक्तिगत रूप से)।

न्यायालय का निर्णय ए. के. सिकरी, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया

1. ये अपीलें चार अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई हैं, जिन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या II, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत मामले संख्या 183/2007 में अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 468, 420 और 500 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत दर्ज की गई है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायत का संज्ञान लिया और अपीलार्थियों को तलब किया। अपीलार्थीओं (जिन्हें आरोपी संख्या 3, 4, 5 और 6 के रूप में प्रस्तुत किया गया था) ने उक्त समन आदेशों को चुनौती दी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में सीआरपीसी) के तहत याचिका दायर करके शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया। चूंकि उनके अनुसार शिकायत में आरोप आईपीसी के उपरोक्त प्रावधानों के तहत कोई अपराध नहीं बनाते हैं; शिकायतकर्ता को न तो सुने जाने का अधिकार था और न ही ऐसी किसी शिकायत को दर्ज करने का कोई कानूनी दर्जा था; अपीलार्थी लोक सेवक और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उनके खिलाफ ऐसी कोई आपराधिक कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 197 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के बिना शुरू नहीं की जा सकती थी। और शिकायत न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और उल्लंघन था जो शिकायतकर्ता द्वारा सिविल उपायों को समाप्त करने के बाद दायर किया गया था जिसमें वह विफल रहा था। उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के बाद, अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई उपरोक्त दलीलों में से किसी में भी कोई योग्यता नहीं पाई है और परिणामस्वरूप, उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

2. इससे पहले कि हम अपीलार्थीओं की प्रस्तुतियों की ओर ध्यान आकर्षित करें, उच्च न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिया गया था उसकी दर्पण छवि है, शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत दर्ज करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों और घटनाओं को देखना उचित होगा। ये निम्नानुसार हैं:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में 'सीएसईबी') ने निविदा (एनआईटी) आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन सं. टी-136/2004 दिनांक 02.06.2004 को जारी किया जो हेसेडियो थर्मल पावर स्टेशन (कोरबा वेस्ट) में एचईए. इग्निशन सिस्टम की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, परीक्षण, आपूर्ति, निर्माण और कमीशन की दिशा में अपने काम के लिए था। इसके तहत प्राप्त आवेदनों को क्रमिक रूप से तीन चरणों में संसाधित किया जाना आवश्यक था; अर्थात, भाग-I (ईएमडी); भाग-II (तकनीकी-वाणिज्यिक मानदंड) और भाग-III (प्री बिड)। यहाँ प्रत्यर्थी ने निविदा दस्तावेज़ के लिए अनुरोध करते हुए मैसर्स कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (सीईआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 26.08.2004 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसके साथ अधूरे दस्तावेज थे अर्थात पूर्व कार्य और अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी संख्या 3 के खिलाफ दिनांक 06.09.2004 की शिकायत की जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी को निविदा दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे। इसके बाद कई पत्रों में निविदा दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया गया। उन्हें सूचित किया गया कि यहां अपीलार्थीओं या अन्य अधिकारियों पर दबाव डालने के बजाय, उन्हें निविदा की पूर्व-योग्यता शर्त के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। इसके जवाब में, अपने पत्र दिनांक 05.11.2004 पत्र के माध्यम से, प्रत्यर्थी ने झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में 'जेएसईबी') द्वारा दिए गए कराया आदेश दिनांक 28.01.2002 की एक प्रति दायर की और बाद में अन्य दस्तावेजी साक्ष्य (कार्य रिपोर्ट) की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। इस तरह के आश्वासन पर, प्रत्यर्थी को निविदा दस्तावेज जारी किए गए थे। प्रत्यर्थी ने अपने पत्र दिनांक 08.12.2004 के माध्यम से उल्लेख किया कि कार्य रिपोर्ट भाग-II में संलग्न थी। हालाँकि, उक्त रिपोर्ट संलग्न नहीं पाई गई और सीएसईबी से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बाद भी, प्रत्यर्थी ने जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। चूंकि प्रत्यर्थी ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए, इसलिए सीएसईबी ने

प्रत्यर्थी के कार्य के बारे में जेएसईबी के मुख्य अभियंता (शिकायत में आरोपी संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत) से सूचना मांगी। इसमें अपीलार्थी संख्या 2 को भी जेएसईबी से वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। जेएसईबी के अधिकारियों से मिलने के बाद, अपीलार्थी संख्या 2 ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कार्य संतोषजनक नहीं थे क्योंकि उनमें कई दोष पाए गए थे। अपीलार्थियों के अनुसार, एसई (ईटी एंड आई) केडब्ल्यू (सीएसईबी) से तकनीकी विशेषज्ञता भी मांगी गई थी और पाया गया कि प्रत्यर्थी एसई (ईटी एंड आई) केडब्ल्यू पत्र दिनांक 04.02.2005 के तकनीकी जांच और तुलनात्मक डेटा के अनुसार तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं था। उस आधार पर, प्रत्यर्थी की निविदा खारिज कर दी गई थी। अपीलार्थीओं का कहना है कि अपने पक्ष में निविदा नहीं मिलने पर प्रत्यर्थी ने राज्य सरकार सहित विभिन्न मंचों पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायतें कीं, जिसने सीएसईबी को जांच करने का आदेश दिया। सीएसईबी ने 21.02.2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि ऐसी कोई अनियमितता नहीं थी और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद प्रत्यर्थी ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। इस स्तर पर, प्रत्यर्थी ने सीएसईबी के खिलाफ सिविल न्यायाधीश वर्ग-II, कोरबा के समक्ष सिविल वाद (26-ए/06) दायर किया। हालांकि, प्रत्यर्थी ने उक्त मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। किसी भी मामले में वह निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ और तदनुसार 12.09.2006 को गैर-अभियोजन के आधार पर वाद खारिज कर दिया गया। यहाँ प्रत्यर्थी ने उसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 2951/2006 दायर की जिसे 25.06.2007 को खारिज कर दिया गया। यहां तक कि रिट याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज करते हुए कि यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग था, 25,000/- रुपये की लागत भी लगाई गई थी। इसके बाद, प्रत्यर्थी द्वारा एसएलपी संख्या 15897/2007 को प्राथमिकता दी गई जिसे भी दिनांक 14.09.2007 के आदेश से खारिज कर दिया गया। इन उपायों के

समाप्त होने के बाद, हालांकि असफल, प्रत्यर्थी ने के.के.नागर पी.एस, थिरुचरपल्ली, तमिलनाडु के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने इसे इस आधार पर दर्ज करने से इनकार कर दिया कि यह एक सिविल विवाद है। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष भा.दं.सं. सी. की धारा 120-बी, 468, 420 और 500 के तहत उक्त आपराधिक शिकायत दायर की, जिसे सी.सी.संख्या 183/07 के रूप में दर्ज किया गया था और विचारण न्यायालय ने इसमें अपीलार्थीओं और आरोपी संख्या 1 (सफल बोलीदाता) और आरोपी संख्या 2 (तत्कालीन मुख्य अभियंता, जेएसईबी) को सम्मन जारी किया। उक्त शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली अपीलार्थियों की याचिकाओं को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो हमारे समक्ष आक्षेपित है।

3. उक्त शिकायत को पढ़ने से प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए निम्नलिखित व्यापक आरोपों का पता चलता हैः

(क) प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता का आरोप है कि अपीलार्थीओं और आरोपी नंबर 1 (सफल बोलीदाता) और आरोपी नंबर 2 (तत्कालीन मुख्य अभियंता, जेएसईबी) ने शिकायतकर्ता की कंपनी को बदनाम करने के लिए गुप्त रूप से साजिश रची थी और उक्त उद्देश्य के लिए, वे लगातार संपर्क में थे ताकि उक्त कार्य रिपोर्ट सह प्रमाण पत्र बनाया जा सके, जिसे आरोपी नंबर 2 द्वारा जारी किया गया था।

(ख) प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त साजिश प्रथम अभियुक्त और इसमें अपीलार्थीओं द्वारा किए गए एक समझौते के साथ शुरू हुई और उन्होंने उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 28.12.2004 बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए, आरोपी नंबर 2 से संपर्क किया गया था ताकि पत्रातु थर्मल पावर स्टेशन (संक्षेप में 'पीटीपीएस') और जेएसईबी के साथ

आपूर्ति और सेवा संबंध के संदर्भ में सीईआई (शिकायतकर्ता की कंपनी) को पूरी तरह से बदनाम करने वाले प्रमाण पत्र को तैयार किया जा सके।

(ग) प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त प्रमाणपत्र सह रिपोर्ट झूठी, मनगढ़ंत, प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण है और यह शिकायतकर्ता और उसके अधिकारियों की पीटीपीएस और जेएसईबी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त के विपरीत है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उक्त कारणों से आरोपी नंबर 2 को उनके पद से हटा दिया गया था।

(घ) प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस तरह के प्रमाण पत्र सह रिपोर्ट के संदेह पर, शिकायतकर्ता सीएसईबी गया और उसी के बारे में सत्यापन करने पर, उसने पाया कि उक्त निविदा शिकायतकर्ता की कंपनी के खिलाफ पहले आरोपी की कंपनी को दी जा रही थी और इसलिए उसने इस तरह के प्रमाण पत्र को सत्यापित करने और रद्द करने के लिए जेएसईबी के मुख्य सचिव और अध्यक्ष को एक पत्र लिखा। उन्होंने सीएसईबी के कई अधिकारियों को भी लिखा।

(ङ) प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त प्रमाणपत्र शिकायतकर्ता की कंपनी के खिलाफ मानहानिकारक है और शिकायतकर्ता कंपनी की छवि खराब करके आरोपी नंबर 1 का पक्ष लेने का एक कच्चा प्रयास है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इससे कोरबा में बॉयलर प्लांट इकाइयों के लिए अनुबंध प्राप्त करने का उचित मौका लूटकर शिकायतकर्ता की कंपनी को गलत नुकसान हुआ।

4. प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थीओं ने

अन्य बातों के साथ साथ तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा भा.दं.सं. सी. की धारा 120-बी, 468, 420 और 500 के तहत लगाए गए आरोप आरोपी संख्या 1 के पक्ष में निविदा देने से संबंधित हैं जिसमें प्रत्यर्थी भी एक प्रतिस्पर्धी पक्ष था। यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त शिकायत एक विचार के बाद दर्ज की गई है, जो निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद में विफल रही है जिसे खारिज कर दिया गया था और इसी तरह, आरोपी संख्या 1 के पक्ष में अनुबंध के पुरस्कार को चुनौती देने के असफल प्रयास के बाद क्योंकि प्रत्यर्थी की रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, तिरुचिरापल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज करना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं था। अपीलार्थीओं ने यह भी तर्क दिया कि यहाँ प्रत्यर्थी को उक्त शिकायत को बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है और न ही कोई कानूनी दर्जा है, क्योंकि सीईआई एक पंजीकृत कंपनी नहीं है, जिसकी कानूनी इकाई है। अपीलार्थीओं ने आगे नरेश कुमार मदन बनाम एम.पी. राज्य (2007) 4 एससीसी 766 पर भरोसा किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विद्युत बोर्ड में काम करने वाला एक कर्मचारी 'लोक सेवक' की परिभाषा के तहत आता है और महाराष्ट्र राज्य बनाम सुब्बाराव, (1993) 2 एससीसी 567 इस प्रस्ताव के लिए कि एक लोक सेवक पर अभियोजन चलाने के लिए धारा 197 सी.आर.पी.सी के तहत उपयुक्त प्राधिकारी से मंजूरी आदेश की अनुपस्थिति में, कार्यवाही को दूषित करता है।

5. प्रत्यर्थी ने यह तर्क देते हुए उपरोक्त प्रस्तुतियों का भंगन किया कि अपीलार्थीओं ने जानबूझकर साजिश रची थी और शिकायतकर्ता के खिलाफ अपराध किए थे और इसलिए उन्हें प्रथम अभियुक्त की निविदा प्रतिग्रहण करना करने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा को अप्रतिग्रहण करना करने में अभियुक्त संख्या 2 (मुख्य अभियंता, जेएसईबी) के साथ अपीलार्थीओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। यह तर्क दिया गया कि उन्होंने साजिश रची और

शिकायतकर्ता के दावे को अप्रतिग्रहण करना करने के विचार के साथ झूठा दस्तावेज बनाया। प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष पहले की कार्यवाही में एक कंपनी के रूप में शिकायतकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठाया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना दिमाग लगाया था और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी को उक्त शिकायत दर्ज करने के लिए कानूनी दर्जा मिला है, आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान लिया था। यह भी तर्क दिया गया कि जहां तक वर्तमान शिकायत का संबंध है, धारा 197 सी.आर.पी.सी के तहत मंजूरी प्राप्त करने का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि अभियुक्तों पर साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और मानहानि का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत में उनका आरोप प्रमाण पत्र-सह-रिपोर्ट दिनांक 28.12.2004 के मनगढ़ंत होने से संबंधित है जिसका उपयोग उनकी निविदा को अप्रतिग्रहण करना करने में उनके खिलाफ किया गया था और पहले आरोपी को काम का पुरस्कार दिया गया था। इसलिए, उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपराध किए और प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

6. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की याचिका को खारिज करते हुए दर्ज किया किः

(क) जहाँ तक धारा 197 सी.आर.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी 'लोक सेवक' हैं। इसने यह भी कहा कि यदि अपीलार्थियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 120-बी, 468, 420 और 500 के तहत आरोप उनके कर्तव्य के निर्वहन द्वारा जुड़े हैं अर्थात यदि उक्त कार्यों का उनके कर्तव्य के निर्वहन के साथ उचित संबंध है तो धारा 197 की प्रयोज्यता पर भंग नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, शिकायत में आरोपों को देखने पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि

भले ही अपीलार्थी "लोक सेवक" हैं, उनके द्वारा किए गए कथित अपराध संज्ञेय अपराध हैं जो उनके सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं हैं, जिसमें आपराधिक विश्वासघात का घटक तत्वों में द्वारा एक के रूप में पाया जाता है और इसलिए धारा 197 सी.आर.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं।

(ख) यह भी देखा गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में साक्ष्य दर्ज किया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके बाद ही विचारण न्यायालय यह निर्णय ले सकती है कि आरोपी संख्या 2 और इसमें अपीलार्थीओं की साजिश के साथ प्रमाण पत्र के झूठ होने के आरोप सही हैं या नहीं।

7. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विचार के लिए मुख्य रूप से दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं अर्थात्ः

(क) क्या अपीलार्थियों, जो स्वीकृत रूप से लोक सेवक हैं, पर अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी संहिता की धारा 197 के तहत अनिवार्य है?

(ख) क्या इस मामले के तथ्यों पर, प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत सिविल वाद में लड़ाई हारने के बाद प्रेरित और विचारशील है और कानून का दुरुपयोग करने के बराबर है?

हम यह टिप्पणी करना चाहेंगे कि इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और आख्यान एक दूसरे से जुड़े होंगे, जैसा कि हम इसके बाद चर्चा के साथ आगे बढ़ने पर स्पष्ट हो जाएगा।

8. इस उद्देश्य के लिए, हम सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय ने स्वयं नरेश कुमार मदन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया है कि अपीलार्थी भा.दं.सं. सी. की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवकों के विवरण के दायरे में आते हैं। इनसे निम्नलिखित टिप्पणियाँ उद्धृत की गई हैंः

> राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को सार्वजनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। वे सार्वजनिक प्राधिकारी हैं। किसी न किसी रूप में उनकी कार्रवाई से विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं के लिए सिविल या बुरे परिणाम हो सकते हैं। वे किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं। उन्हें बोर्ड के उपभोक्ताओं के घर में प्रवेश करने का अधिकार है। यह केवल उन शक्तियों के उचित और प्रभावी प्रयोग के लिए है, अधिनियम में प्रावधान है कि वे लोक सेवक होंगे, इसलिए उन कर्मचारियों के पक्ष में एक कानूनी कल्पना बनाई गई है, जब वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करते हैं या कार्य करने का इरादा रखते हैं। भारतीय दंड संहिता लोक सेवकों के लिए विभिन्न व्यक्तियों को संदर्भित करती है। हालाँकि, यह सुविस्तृत नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे अधिनियम के संदर्भ में लोक सेवक हो सकता है। यद्यपि हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, जो अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित सरकार की सेवा या वेतन में है, वह भी उसके दायरे में आएगा। 1988 के अधिनियम की धारा 2(1)(सी) केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम की सेवा या वेतन में किसी व्यक्ति को भी अपने दायरे में लाती है।"

9. सवाल संहिता की धारा 197 की प्रयोज्यता का है। उक्त प्रावधान जिसके बारे में हम चिंतित हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन- (1) जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था, जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान -
>
> (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, यथास्तिथि नियोजित है या अभिकथित अपराध के किये जाने के समय नियोजित था, केंद्रीय सरकार की;
>
> (ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, यथास्तिथि, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किये जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की, पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं।"

10. यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई अपराध किसी लोक सेवक द्वारा किया गया है, जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा पद से हटाया नहीं जा सकता है, तो न्यायालय को इस प्रावधान में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अलावा ऐसे अपराध का संज्ञान लेने से रोक दिया जाता है।

11. हालाँकि, मंजूरी आवश्यक है यदि लोक सेवक के खिलाफ कथित अपराध उसके द्वारा "अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए अभिप्रेत" किया गया है। यह पता लगाने के लिए कि क्या कथित अपराध अपने आधिकारिक कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए किया गया है या कार्य करने के लिए अभिप्रेत है, इस न्यायालय द्वारा डॉ. बुधिकोटा सुब्बाराव (उपरोक्त) में निम्नलिखित मानदंड निम्नलिखित शब्दों में प्रदान किए गए हैंः

> "यदि तथ्यों पर, इसलिए, यह प्रथमदृष्टया पाया जाता है कि जिस कार्य या चूक के लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था, उसका अपने कर्तव्य के निर्वहन के साथ उचित संबंध था, तो इसे आधिकारिक माना जाना चाहिए जिसके लिए संहिता की धारा 197 की प्रयोज्यता पर विवाद नहीं किया जा सकता है।"

12. इस सिद्धांत को रघुनाथ अनंत गोविलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कुछ और विस्तार से समझाया गया था, जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5453/2007 में 08.02.2008 को निम्नलिखित तरीके से किया गया था:

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के लागू होने के सवाल पर, दो मामलों में निर्धारित सिद्धांत, श्रीकंठिया रामय्या मुनिपल्ली बनाम बॉम्बे राज्य और अमरीक सिंह बनाम पेप्सू राज्य, इस प्रकार थेः
>
> लोक सेवक द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है और न ही उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए, जबकि वह वास्तव में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में लगा

हुआ है, लेकिन यदि शिकायत किया गया कार्य सीधे उसके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित है ताकि, यदि सवाल किया जाए, तो यह दावा किया जा सके कि यह कार्यालय के आधार पर किया गया है, तो मंजूरी की आवश्यकता होगी।

अतः वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामले में जिन कृत्यों की शिकायत की गई है, वे सीधे तौर पर तीन लोक सेवकों के आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित थे। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के साथ पठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश के अपराध का संबंध है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) का भी संबंध है, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में उल्लिखित प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है। संक्षेप में कहें तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय आपराधिक साजिश में शामिल होना या आपराधिक कदाचार में शामिल होना लोक सेवक के कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता कोई बाधा नहीं है।"

13. इसी तरह, शंभू नाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (1997) 5 एससीसी 326 में, न्यायालय ने इस विषय को निम्नलिखित तरीके से निस्तारित किया:

"5. सवाल यह है कि जब लोक सेवक पर अभिलेख के मनगढ़ंत या सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग आदि का अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में काम किया था? लोक सेवक का यह आधिकारिक कर्तव्य नहीं है कि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों को आगे बढ़ाने या उनके निर्वहन में गलत रिकॉर्ड बनाए और सार्वजनिक

धन आदि का दुरुपयोग करे। आधिकारिक क्षमता केवल उसे अभिलेख गढ़ने या सार्वजनिक निधि आदि का दुरुपयोग करने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक ही लेन-देन के दौरान किए गए अपराध के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है या अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा माना गया था। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि मंजूरी के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।"

14. उपरोक्त मामलों का अनुपात, जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, यह है कि अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भी, यदि कोई लोक सेवक आपराधिक साजिश में प्रवेश करता है या आपराधिक कदाचार में लिप्त होता है, तो उसकी ओर से इस तरह के दुराचार को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में एक कार्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए, संहिता की धारा 197 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया जाएगा। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर याचिकाओं को ठीक इन टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया है, अर्थात् आरोप झूठे रिकॉर्ड बनाने से संबंधित हैं जिन्हें अपीलार्थी के सामान्य आधिकारिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने कानून के प्रस्ताव को सही ढंग से स्पष्ट किया है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों पर, इसे सही ढंग से लागू किया गया है। यदि कोई शिकायत में लगाए गए आरोपों को अकेले आरोपों के रूप में देखता है, तो शायद उच्च न्यायालय ने जो कहा है वह उचित प्रतीत हो सकता है। हालाँकि, जिन परिस्थितियों के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, उनकी थोड़ी गहरी जांच से यह पता चलेगा कि झूठे रिकॉर्ड को गढ़ने का आरोप स्पष्ट रूप से एक विचार के बाद है और यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी ने पूरे मामले को आपराधिकता

का रूप देने के एकमात्र उद्देश्य के साथ इस तरह के विश्वास आरोप लगाने का विकल्प चुना है, जो अन्यथा सिविल प्रकृति का था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी ने वास्तव में उस अनुबंध के अधिनिर्णय के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे के रूप में सिविल कार्रवाई शुरू की थी जिसमें वह विफल रहा था। सिविल न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। प्रत्यर्थी की याचिका थी कि उसकी निविदा को अस्वीकार करने और आरोपी नंबर 1 को अनुबंध देने में विभाग की कार्रवाई अवैध और प्रेरित थी। रिट याचिका को भी लागत के साथ खारिज कर दिया गया था। इन आदेशों को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद ही इस आरोप के साथ आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है कि आरोपी नंबर 1 का समर्थन दिनांक 28.12.2004 का झूठा प्रमाण पत्र बनाकर किया जाता है। हम इस चर्चा को कुछ विस्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे।

15. जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, सीएसईबी द्वारा निविदा जारी की गई थी और सीईआई उन पक्षों में से एक था जिसमे प्रत्यर्थी द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत की थी। हालांकि, निविदा शर्तों में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया था और बोली जमा करने के योग्य बनने और उस पर विचार करने के लिए उन शर्तों को पूरा करना आवश्यक था। अपीलार्थियों के अनुसार, प्रत्यर्थी की निविदा इस आधार पर खारिज आदेश दी गई थी कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्रातु ताप विद्युत केंद्र, पत्रातु, झारखण्ड में स्थापित संयंत्र और पुर्जे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जेएसईबी से निविदा समिति को यह जानकारी मिली थी। जब दिसंबर, 2004 में सीएसईबी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी, तो निविदा समिति ने यह विचार लिया कि प्रत्यर्थी ने पूर्व-योग्यता शर्तों को पूरा नहीं किया और उसकी निविदा को खारिज कर दिया। ऐसा करने से पहले, प्रत्यर्थी को बार-बार कार्य रिपोर्ट भेजने के लिए कहा जाता था, जिसका उसने वादा किया था, लेकिन वह तब भी पालन करने में विफल रहा जब उसने आवश्यक कार्य करने का आश्वासन दिया

था। वास्तव में, यह स्वयं प्रत्यर्थी की उस बोली को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि यह निविदा शर्तों का पालन नहीं आदेश रहा था। फिर भी, प्रत्यर्थी के दावे को सत्यापित करने और गुण-दोष के आधार पर उसकी बोली पर विचार करने के लिए, हालांकि इसकी सख्त आवश्यकता नहीं थी, अपीलार्थी आर.सी.जैन को जेएसईबी से वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने जेएसईबी के अधिकारियों से मुलाकात की और इस आशय की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पत्रातु ताप विद्युत केंद्र में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक नहीं था। यहां तक कि उक्त विद्युत केंद्र के महाप्रबंधक श्री बी.एम. राम ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.12.2004 प्रस्तुत की, जिसमें यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी द्वारा आपूर्ति की गई स्कैनिंग प्रणाली में दोषों के कारण उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था और उक्त विद्युत बोर्ड प्रत्यर्थी द्वारा आपूर्ति किए गए पुर्जों से संतुष्ट नहीं था। उपरोक्त सामग्री के बावजूद, निविदा समिति ने सावधानी के साथ काम किया और यहां तक कि तकनीकी विशेषज्ञता भी मांगी गई। यहां तक कि तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी प्रत्यर्थी के खिलाफ गई क्योंकि यह राय थी कि प्रत्यर्थी तकनीकी जांच और तुलनात्मक डेटा पर तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं था। उपरोक्त सामग्री के आधार पर, प्रत्यर्थी का निविदा दस्तावेज नहीं खोला गया और उसे वापस नहीं किया गया और उसी के अनुसार उसे सूचित किया गया। यह सब स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों को आगे बढ़ाने और उनके निर्वहन में हुआ है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हमारा विचार है कि अभिलेखों को मनगढ़ंत बनाने के आरोप केवल एक सिविल मामले को आपराधिकता का रंग देने के लिए एक विचार के रूप में शरारतपूर्ण तरीके से लगाए गए हैं।

16. जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्यर्थी ने इस आधार पर अपने निविदा दस्तावेजों को वापस करने के विद्युत बोर्ड के फैसले को चुनौती देते हुए सिविल वाद भी दायर किया था कि वे निविदा की पूर्व-योग्यता शर्तों के अनुसार नहीं थे। इस प्रकार

उन्होंने सिविल उपचार का सहारा लिया था। हालाँकि, वह इसमें विफल रहे क्योंकि उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की और तदनुसार इसे गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया। यह सामान्य बात है कि एक बार वाद वापस लिए जाने के बाद, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 1 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, जब आदेश IX नियम 8 सी. पी. सी. के तहत वाद खारिज किया जाता है, तो आदेश IX नियम 9 के तहत नया वाद वर्जित होता है। कानूनी निहितार्थ यह होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा अपनी निविदा पर विचार नहीं करने के निविदा समिति के निर्णय को चुनौती देने का प्रयास त्रुटिहीन रहा। यहां तक कि जब प्रत्यर्थी ने स्वयं सिविल वाद में बर्खास्तगी के आदेश को आमंत्रित किया, तो दिलचस्प रूप से, उसने सिविल न्यायालय में पारित आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की, जिसमें गैर-अभियोजन के कारण उसका वाद खारिज कर दिया गया था, लेकिन उसी को उच्च न्यायालय द्वारा 25.06.2007 को भी खारिज कर दिया गया था और यहां तक कि प्रत्यर्थी पर 25,000/- रुपये की लागत भी लगायी गई थी क्योंकि उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 'न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग' माना गया था। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत एसएलपी को भी इस न्यायालय द्वारा 14.09.2007 को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही प्रत्यर्थी ने आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसमें से वर्तमान कार्यवाही निकलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपनी शिकायत में प्रत्यर्थी को यह आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत को रंग देने का अधिकार है कि इसमें अपीलार्थीओं ने अभिलेखों को गढ़ा है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों पर, प्रत्यर्थी के इस आरोप से बचना मुश्किल हो जाता है और हमें एक विचित्र भावना मिलती है कि इन आरोपों के साथ प्राथमिकी की सामग्री सिविल कार्यवाही में लड़ाई हारने के बाद प्रत्यर्थी की एक पोस्टस्क्रिप्ट है, जिसे उसने अपनी निविदा को अस्वीकार करने में विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए निकाला था। जब वह उक्त प्रयास में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने

जालसाजी के आरोप लगाए। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक शिकायत दर्ज करने में प्रत्यर्थी की कार्रवाई प्रामाणिक नहीं है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और उल्लंघन करने के बराबर है।

17. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 पूरक (1) एससीसी 335 में, इस न्यायालय ने ऐसे सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिन पर न्यायालय सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। ये निम्नानुसार हैंः

> "102 (1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।
>
> (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।
>
> (3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।
>
> (4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना

पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत माना गया है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है संबंधित संहिता या अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

वर्तमान मामले में सिद्धांत संख्या 6 और 7 स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।

18. ऊपर वर्णित और समझाई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह भी विचार है कि प्रत्यर्थी द्वारा सिविल प्रकृति वाले मामले को आपराधिक अभियोजन में बदलने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के मामले में, उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करने में उचित ठहराया जाता। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड और अन्य, (2006) 6 एससीसी 736 के मामले में निर्णय

का उल्लेख करना लाभप्रद होगा, जिसमें न्यायालय ने वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित मामलों में भी आपराधिक शिकायतें दर्ज करने की इस प्रवृत्ति पर प्रतिकूल टिप्पणी की है, जिसके लिए सिविल उपचार उपलब्ध है या जिसका लाभ उठाया गया है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस संबंध में न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दें जाता हैः

> "13. जबकि इस मुद्दे पर, विशुद्ध रूप से सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की व्यावसायिक हलकों में बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से एक प्रचलित धारणा के कारण है कि सिविल कानून उपचार समय लेने वाले हैं और ऋणदाताओं/लेनदारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति कई पारिवारिक विवादों में भी देखी जाती है, जिससे विवाह/परिवार अपरिहार्य रूप से टूट जाते हैं। ऐसी धारणा भी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह आपराधिक अभियोजन में उलझ सकता है, तो आसन्न समझौते की संभावना है। सिविल विवादों और दावों को निपटाने के किसी भी प्रयास की, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, आपराधिक अभियोजन द्वारा से दबाव बनाकर निंदा की जानी चाहिए और हतोत्साहित किया जाना चाहिए। जी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2000) 2 एससीसी 636 में, इस न्यायालय ने कहाः (एससीसी पेज 643, पैरा 8)
>
> "यह देखा जाना चाहिए कि क्या किसी मामले को, जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का है, आपराधिक अपराध का कवच दिया गया है। आपराधिक कार्यवाही कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। प्रक्रिया जारी करने से पहले एक आपराधिक

न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी होती है। अभियुक्त के लिए यह एक गंभीर मामला है। इस न्यायालय ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है। इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।"

14. जबकि वैध कारण या शिकायत वाले किसी भी व्यक्ति को आपराधिक कानून में उपलब्ध उपचार की मांग करने से रोका नहीं जाना चाहिए, एक शिकायतकर्ता जो अभियोजन शुरू करता है या जारी रखता है, पूरी तरह से जानता है कि आपराधिक कार्यवाही अनुचित है और उसका उपचार केवल सिविल कानून में निहित है, कानून के अनुसार ऐसी गलत आपराधिक कार्यवाही के अंत में खुद को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। एक सकारात्मक कदम जो न्यायालयों द्वारा निर्दोष पक्षों के अनावश्यक अभियोजन और उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए उठाया जा सकता है, वह है धारा 250 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्ति का अधिक बार प्रयोग करना, जहां वे शिकायतकर्ता की ओर से द्वेष या तुच्छता या गुप्त उद्देश्यों को समझते हैं। जैसा भी हो।"

19. इंदर मोहन गोस्वामी और एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य, (2007) 12 एससीसी 1 में, न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति के क्षेत्र और दायरे को निम्नलिखित शब्दों में दोहरायाः

"23. इस न्यायालय ने कई मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालयों की शक्तियों का क्षेत्र और दायरा निर्धारित

किया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए, जिसके केवल प्रशासन के लिए ही यह मौजूद है, या न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्याय के ऋण से या उसके रूप में कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति है। धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता हैः

(i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी बनाना;

(ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और

(iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना।

24. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह का प्रयोग इस धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाए। न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का अधिकार मौजूद है। यदि अन्याय की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है, तो संविधि में विशिष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति में अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके अन्याय को रोकने में न्याय संगत ठहराया जा सकता है।

तय किए गए मामलों पर चर्चा

25. निम्नलिखित मामलों के संदर्भ से पता चलता है कि न्यायालयों ने लगातार यह विचार रखा है कि उन्हें अन्याय को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए इस असाधारण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। अंग्रेजी न्यायालयों ने भी इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का उपयोग किया है। आम तौर पर यह सहमति है कि क्राउन कोर्ट के पास अपनी प्रक्रिया को दुरुपयोग से बचाने की अंतर्निहित शक्ति है। कॉनेली बनाम डीपीपी., 1 1964 एसी 1254 में लॉर्ड डेवलिन ने कहा कि जहां विशेष आपराधिक कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है, न्यायालय को अभियोग को मुकदमे में आगे बढ़ने की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार है। डीपीपी बनाम हम्फ्रीस, 1977 एसी 1 में लॉर्ड सैल्मन ने अंतर्निहित शक्ति के महत्व पर जोर दिया जब उन्होंने कहा कि यह केवल तभी है जब अभियोजन पक्ष न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है और दमनकारी और परेशान करने वाला है कि न्यायालय के पास हस्तक्षेप करने की शक्ति है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की न्यायालय की शक्ति बहुत संवैधानिक महत्व की है और इसे ईर्ष्या से संरक्षित किया जाना चाहिए।

46. न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक अभियोजन का उपयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में या निजी प्रतिशोध की मांग के लिए या आरोपी पर दबाव बनाने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ नहीं किया जाता है। उपरोक्त मामलों के विश्लेषण पर, हमारी राय है कि निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले एक अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है

और न ही वांछनीय है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों की निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इसे क़ानून में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों और उपरोक्त मामलों में उचित ठहराया जाए। तय कानूनी स्थिति को देखते हुए, विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।"

20. परिणामस्वरूप, इन अपीलों को स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है। नतीजतन, विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान और अपीलार्थियों को अभियुक्त के रूप में बुलाने के आदेश को एततद्वारा अपास्त किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उक्त शिकायत को खारिज कर दिया है। हालांकि लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।